राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष – 03 | अंक – 342 | जौनपुर | शुक्रवार, 01 अगस्त 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

हिमंत बिस्वा सरमा का भी तगड़ा बयान : सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में सात आरोपियों को बरी किए जाने को लेकर गुरुवार को कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि यह फैसला पार्टी के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को उजागर करता है। योगी ने एक्स पर लिखा कि मालेगांव विस्फोट प्रकरण में सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की सजीव उद्घोषणा है। योगी आदित्यनाथ ने आगे लिखा कि यह निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है, जिसने भगवा आतंकवाद जैसा मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों सनातन आस्थावानों, साधु–संतों और राष्ट्रसेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया है। कांग्रेस को अपने अक्षम्य कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कल सदन में भी कहा कि दर्शनशास्त्र के अनुसार हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकते क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देती। लेकिन कांग्रेस के शासन में एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए एक शब्द गढ़ा गया– हिंदू आतंकवाद। भाजपा नेता ने कहा कि हिंदू और आतंक दो विपरीत अवधारणाएँ हैं। हिंदू कभी आतंक में विश्वास नहीं करते और हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। मेरे लिए – यह अत्यंत संतोष की बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में जो कुछ भी कहा, आज मुंबई की एक अदालत ने भी हिंदू आतंक की अवधारणा को ध्वस्त कर दिया और जो भी शहिंदू आतंकश के नाम पर आरोपी थे,।

अमित शाह की दो टूक, कांग्रेस को भी खूब सुनाया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत में आतंकवाद के पतन के कगार पर होने की बात दोहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने संबोधन में कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। पहलगाम नरसंहार और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे वापस लेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की उदार नीतियों और तुष्टिकरण के रवैये ने देश में आतंकवाद को पनपने और फलने–फूलने का मौका दिया। सौभाग्य से, अब हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो केवल दस्तावेजों पर निर्भर रहने के बजाय निर्णायक कार्रवाई करता है, ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के इस आकलन की आलोचना करते हुए कि 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में

पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकवादियों से पाकिस्तान का कोई ठोस संबंध नहीं है, गृह मंत्री ने कहा, षचिदंबरम साहब ने कल कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता कि ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक था। चिदंबरम साहब यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या 1965 और 1971 के युद्ध निर्णायक थे। अगर वे निर्णायक थे, तो आतंकवाद क्यों फैलता रहा? गृह मंत्री ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के 2008 के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने 26धा1 के मुंबई आतंकी हमलों में आरएसएस के शामिल होने की संभावना जताई थी। शाह ने पूछा कि हमारी एजेंसियों को इस बात के सबूत मिले हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान से थे। लेकिन उनके (चिदंबरम के) गृह मंत्री रहते हुए अफजल गुरु को फांसी नहीं दी गई.. . मुंबई आतंकी हमले के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा था।

संक्षिप्त खबरें

बीआरएस विधायकों की अयोग्यता पर तीन महीने में फैसला लें तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वह सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने वाले भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के 10 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर तीन महीने में फैसला करें। प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलबदल राष्ट्रीय चर्चा का विषय रहा है और अगर इसे रोका नहीं गया तो इससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। पीठ ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता पी. कौशिक रेड्डी की एक अपील स्वीकार कर ली, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 22 नवंबर 2024 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एकल न्यायाधीश के पूर्व आदेश में हस्तक्षेप किया गया था। प्रधान न्यायाधीश ने फैसला पढ़ते हुए कहा, '' अयोग्यता की कार्यवाही अध्यक्ष को सौंपने का उद्देश्य अदालतों में होने वाली देरी से बचना है।'' शीर्ष अदालत ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष दलबदल याचिकाओं पर फैसला सुनाते समय एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हैं और इसलिए उन्हें संवैधानिक छूट प्राप्त नहीं होती। विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है। शीर्ष अदालत ने तीन अप्रैल को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

भारत–अमेरिका ट्रेड डिल पर आया शशि थरूर का बयान

अमेरिका, (एजेंसी)। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह एक चुनौतीपूर्ण वार्ता है। हम कई देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका अकेला ऐसा देश नहीं है जिसके साथ बातचीत चल रही हो। यूरोपीय संघ के साथ हमारी बातचीत चल रही है, हमने ब्रिटेन के साथ एक समझौता कर लिया है, और हम अन्य देशों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। अगर हम अमेरिका में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, तो हमें अमेरिका के बाहर अपने बाजारों में विविधता लानी पड़ सकती है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। शशि थरूर ने कहा कि अगर अमेरिका अपनी माँगों को लेकर पूरी तरह से अनुचित है, तो हमें कहीं और जाना होगा। यही भारत की ताकत हैय हम चीन की तरह पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था नहीं हैं। हमारे पास एक अच्छा और मजबूत घरेलू बाजार है। हमें अपने वार्ताकारों को सर्वोत्तम संभव सौदा खोजने के लिए मजबूत समर्थन देना चाहिए। अगर कोई अच्छा सौदा संभव नहीं है, तो हमें पीछे हटना पड़ सकता है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि ट्रंप कोई पारंपरिक राजनेता नहीं हैं। कूटनीति के सामान्य प्रोटोकॉल और अंतर–सरकारी संबंधों के सामान्य नियम काम नहीं करते।

साध्वी प्रज्ञा के बरी होने पर रो पड़ीं उमा भारती

नई दिल्ली, (एजेंसी)। वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी सात आरोपियों को एनआईए अदालत द्वारा बरी किए जाने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया साझा की। भारती ने 31 जुलाई, 2025 के फैसले पर गहरी राहत व्यक्त की, जिसमें 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सबूतों के अभाव में ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य को बरी कर दिया गया। मालेगांव विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उमा भारती ने कहा कि मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे पास शब्दों में बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं। भावुक होते हुए हुए उन्होंने कहा कि जब प्रज्ञा नासिक जेल में थीं, तो मुझे एक पुलिस अधिकारी से पता चला कि उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं उनसे मिलने गई थी, जब कोई नहीं जाता था। जब मैं उनसे मिली, तो मैं रोई। जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, वो किसी भी महिला के लिए सहन करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ कि पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस के नेताओं को क्या सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने भगवा आतंक शब्द को स्थापित करने की कोशिश की?... उनके खिलाफ असाधारण कार्रवाई होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) नेता विनोद बंसल ने कहा कि मालेगांव विस्फोट मामले में आए फैसले ने चार बातें स्पष्ट कर दी हैंरू कांग्रेस आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैय उसने हिंदू या भगवा आतंकवाद का झूठा सिद्धांत गढ़ाय तीसरी, कांग्रेस ने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए असली आतंकवादियों को बचायाय चौथी, निर्दोष हिंदुओं को सताने के लिए कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे के तहत जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। कांग्रेस को हिंदू समुदाय और देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए जिसमें कहा जाए कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने आतंकवादियों का समर्थन किया है और हिंदुओं को फंसाया है, जिससे वह हिंदू विरोधी पार्टी बन गई है। साध्वी प्रज्ञा, सैन्य अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाकर, कांग्रेस ने 2009 का चुनाव जीतने के लिए एक राजनीतिक एजेंडा चलाया. .. राम जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, सोनिया गांधी ने तुरंत कहा कि वे मामले में पक्षकार न होने के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगी।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मिलेगी 2000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 2025–26 से 2028–29 तक 4 साल की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायताश की मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी है। सरकार की ओर से बताया गया है कि वर्ष 2025–26 से 2028–29 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए अनुदान सहायता पर 2000 करोड़ रुपये का परिव्यय किया जाएगा। एनसीडीसी चार वर्षों की अवधि में खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपये जुटा सकेगी। एनसीडीसी की ओर से नई परियोजनाओं की स्थापनाध्संयंत्रों के विस्तार, सहकारी समितियों को ऋण

देने और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देने हेतु निधियों का उपयोग किया जाएगा। सरकार ने बताया है कि इस कदम से देश भर में डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसे विभिन्न क्षेत्रों की 13,288 सहकारी समितियों के 2.9 करोड़ सदस्योंय श्रम और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को लाभ मिलेगा। वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को चार वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है। इस कदम से संगठन को ऋण देने के लिए अधिक धन जुटाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया, ष्एक अच्छे वित्तीय मॉडल को और अधिक समर्थन देने के लिए, मंत्रिमंडल ने एनसीडीसी के लिए चार वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपये की पूंजी अनुदान सहायता को मंजूरी दी। एनसीडीसी 8.25 लाख से अधिक सहकारी समितियों को ऋण देता है, जिनके 29 करोड़ सदस्य हैं। कुल सदस्यों में से 94 प्रतिशत किसान हैं। मंत्री ने कहा कि इस वित्तीय सहायता से एनसीडीसी आगे ऋण देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने में सक्षम हो सकेगी।

कांग्रेस की हिंदू आतंकवाद की साजिश ध्वस्त हो गई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की हिंदू आतंकवाद की साजिश ध्वस्त हो गई है। एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले कर्नल पुरोहित पर आरोप लगाया गया था। प्रज्ञा ठाकुर पर ब्लास्ट में अपनी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके बाद वह चल नहीं सकती थीं। यह विशुद्ध वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस की साजिश थी। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। पूर्व केंद्रीय

मंत्री ने कहा कि आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र आज धराशायी हो गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कर्नल पुरोहित एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था, जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी, उसको फंसाया गया। बहुत ही अच्छी साध्वी, नेत्री प्रज्ञा ठाकुर पर आरोप लगाया गया था कि उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था। उनको 10–12 दिन तक इतना प्रताड़ित किया गया कि बाद में उनका चलना भी मुश्किल हो गया था। भाजपा नेता ने साफ तौर पर कहा कि ये कांग्रेस की एक सोची हुई रणनीति थी, वो भी शुद्ध वोटबैंक के लिए। ये षड्यंत्र धराशायी हुआ, इस पर हमें खुशी भी है और संतोष भी है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और खुशी का भी, क्योंकि यूपीए सरकार ने सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का खेल खेला था। यूपीए सरकार ने आतंकवाद के एक नए रूप को जन्म दिया था, जिसे उन्होंने शहिंदू आतंकवादश कहना शुरू कर दिया था। यूपीए सरकार के इस कथन को सही साबित करने के लिए उन्होंने सनातन प्रवृत्ति के नेताओं को झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया। आज यह सिद्ध हो गया है कि शहिंदू आतंकवादश जैसी कोई चीज नहीं होती... एक हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, और अगर कोई आतंकवादी है, तो वह हिंदू नहीं हो सकता।

सीएम फडणवीस की हुंकार, आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है, ना कभी रहेगा

मुबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को मालेगांव विस्फोट मामले में सात लोगों को बरी किए जाने की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि भगवा का आतंकवाद से न कभी कोई संबंध रहा है और न ही कभी रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, ष्आतंकवाद भगवा न कभी था, न है, न कभी रहेगा।ष मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने आज 2008 में मालेगांव में हुए बम धमाकों में शामिल सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। इस बीच, उप–मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी एनआईए अदालत के

फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। शिंदे ने मराठी में एक्स पर पोस्ट किया, ष्शुरू से ही, शिवसेना ने उन देशभक्तों का खुलकर समर्थन किया है जिन पर मालेगांव विस्फोट मामले में झूठे आरोप लगाए गए थे और उन्हें जेल में डाला गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिवसेना को कभी भी इस बात में कोई संदेह नहीं था कि उनका मुद्दा न्यायसंगत था। कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और अन्य सात व्यक्तियों को इन आरोपों के कारण भारी मानसिक और शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी। हिंदू समुदाय इस अन्याय को कभी नहीं भूलेगा। 2010 में, तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने 2008 के

मोदी शाह राजनाथ ने संसद में पीओके पर बयान देकर क्या संदेश दिया है

नई दिल्ली, (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हुई चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार पीओके (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) के मुद्दे को केवल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देख रही, बल्कि इसे अपनी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह विपक्ष पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि "पीओके पर कब्जा होने का अवसर किस सरकार ने दिया?", उसने कांग्रेस को सीधा ऐतिहासिक जिम्मेदारी के घेरे में ला खड़ा किया। यह बयान न केवल अतीत की राजनीतिक गलतियों की याद दिलाता है, बल्कि भाजपा को राष्ट्रवाद की ठोस जमीन पर खड़ा करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए साफ कह दिया कि भाजपा सरकार पीओके को वापस लाएगी। यह बयान चुनावी दृष्टि से भाजपा के लिए बड़ा हथियार बन सकता है, क्योंकि यह जनता में यह संदेश देता है कि मौजूदा सरकार केवल कड़ी भाषा नहीं बोल रही, बल्कि निर्णायक कार्रवाई का भी इरादा रखती है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीओके के लोगों की 'घर वापसी' की उम्मीद जताकर एक भावनात्मक और रणनीतिक संदेश दिया। यह बयान बताता है कि सरकार इस मुद्दे को केवल सैन्य ऑपरेशन या सीमित राजनीतिक बहस तक नहीं रख रही, बल्कि इसे एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में स्थापित कर रही है। तीनों बयानों को मिलाकर देखें तो भाजपा ने पीओके को लेकर विपक्ष को घेरने के साथ–साथ जनता के बीच एक बार फिर राष्ट्रवाद की लहर पैदा करने की कोशिश की है। यह रणनीति न केवल कांग्रेस पर ऐतिहासिक सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि भविष्य में पीओके को लेकर कोई ठोस कदम भाजपा की राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडा का हिस्सा हो सकता है। जहां तक यह सवाल है कि क्या च्वज्ञ के लोग भारत के साथ आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि वहां इस समय आर्थिक विकास की स्थिति बहुत खराब है। बेरोजगारी, आधारभूत ढाँचे की कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा में गिरावट जैसे मुद्दे गंभीर हैं। वहां के संसाधनों का दोहन पाकिस्तान जबरदस्त तरीके से कर रहा है लेकिन स्थानीय जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। वहां लोग मानते हैं कि भारत के जम्मू–कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों की तुलना में उन्हें पाकिस्तान सरकार से अपेक्षित सुविधाएँ नहीं मिलतीं। खुले तौर पर भारत के साथ मिलने की मांग बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ऐसा कहना वहाँ बेहद खघ्तरनाक हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियाँ इसे देशद्रोह मानती हैं। लेकिन स्थानीय नाराजगी पाकिस्तान सरकार और फौज के खिलाफ बहुत गहरी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां के लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं। इसके अलावा, च्वज्ञ में एक वर्ग ऐसा भी है जो न तो पाकिस्तान में रहना चाहता है और न ही भारत से जुड़ना चाहता है। वे "आजाद कश्मीर" या स्वतंत्र राज्य की मांग करते हैं। इसके लिए वहाँ कई संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इन्हें दबा देता है। पीओके में भारत के प्रति धारणा कई बार पाकिस्तान की प्रचार मशीनरी से भी प्रभावित होती है, जिसमें भारत को एक ष्दुश्मन देशष के रूप में दिखाया जाता है। हालाँकि, भारत द्वारा जम्मू–कश्मीर में विकास परियोजनाओं, सड़कें, मेडिकल सुविधाएँ, टूरिज्म और शिक्षा में सुधार की खबरें तेजी से वहाँ के लोगों तक पहुँच रही हैं। कई रिपोर्टों में बताया गया है कि लोग भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि वे बेहतर जीवन स्तर और स्वतंत्रता की उम्मीद करते हैं। हम आपको बता दें कि पिछले एक–दो वर्षों में च्वज्ञ में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान सरकार और फौज के खिलाफ प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने महँगाई, बिजली संकट, टैक्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। कई नारे ष्पाकिस्तानी फौज बाहर जाओष और ष्हमें हमारा हक दोष जैसे थे। यह दिखाता है कि पाकिस्तान के प्रति यहां असंतोष गहरा है। अधिकांश लोग अधिक आजादी, बेहतर शासन और आर्थिक अवसर चाहते हैं। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि पीओके में पाकिस्तान के विरोध में गहरी होती नाराजगी एक दिन ज्वालामुखी का रूप ले सकती है और ऐसे में भारत के लिए आगे की राह बेहद आसान हो जायेगी।

संपादकीय

ट्रंप का टैरिफ युद्ध

राष्ट्रपति पद संभालने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संरक्षणवादी एजेंडे के साथ ही चीन, कनाडा व मैक्सिको पर भारी–भरकम टैरिफ थोपकर व्यापार युद्ध की शुरुआत कर दी है। ट्रंप के फैसले से वैश्विक बाजारों में भूचाल है। इन तीनों देशों द्वारा इसका जबाव देने की घोषणा से विश्व व्यापार युद्ध शुरू होने की आशंका पैदा हो गई है। दरअसल, अमेरिका ने अपने शीर्ष व्यापारिक सहयोगी कनाडा व मैक्सिको पर 25 फीसदी और चीनी सामानों पर 10 प्रतिशत टैफिक थोपकर उन्हें आर्थिक प्रतिशोध हेतु बाध्य कर दिया है। कनाडा ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है तो मैक्सिको भी ऐसा मन बना रहा है। वहीं चीन पिछली टैरिफ लड़ाइयों से परेशान होकर रणनीतिक प्रतिशोध को तैयार है। वह इस मामले को विश्व व्यापार संगठन तक ले जाने की बात कर रहा है। हालांकि, भारत फिलहाल ट्रंप की संरक्षणवादी कार्रवाई से बचा नजर आता है। भारत ने टैरिफ कटौती की दिशा में कदम उठाते हुए ट्रंप के उस टैरिफ दुरुपयोग के आक्षेप से बचने का प्रयास किया है, जिसको लेकर ट्रंप भारत को निशाने पर लेते हैं। दरअसल, भारत में शीर्ष तीस अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क मसलन कच्चे पेट्रोलियम से लेकर हार्ले–डेविडसन मोटर साइकिल तक पर मामूली टैरिफ हैं। निस्संदेह, यह रणनीतिक कदम न केवल तत्काल अमेरिकी प्रतिशोध को रोकता है बल्कि वैश्विक आपूर्ति शृंखला में एकीकृत होने के लिये भारत की प्रतिबद्धता का भी संकेत देता है। जैसा कि केंद्रीय बजट 2025–26 में रेखांकित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत अमेरिकी व्यापार घाटे में केवल 3.2 प्रतिशत का ही कारक है। इसकी वजह यह भी है कि भारत के तेजी से बढ़ते फार्मास्युटिकल और कीमती धातुओं के निर्यात फिलहाल कमजोर बने हुए हैं। यह अच्छी बात है कि ट्रंप ने पहले टैरिफ वार से भारत को राहत दी है, लेकिन वैश्विक व्यापार युद्ध से भारत में विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है। असर रुपये की सेहत पर भी पड़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा से द्विपक्षीय व्यापार खिड़की खुलने की संभावना है। वहीं ट्रंप की इस कार्रवाई का एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि सामान पर टैरिफ बढ़ाए जाने से चीनी उत्पाद महंगे होंगे, तो भारतीय निर्यातक अमेरिका बाजार में नये अवसर तलाश सकते हैं। खासकर कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो पार्ट्स के क्षेत्र में। लेकिन इसके बावजूद भारत को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। इस टैरिफ जंग का एक पहलू यह भी कि अमेरिका में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। ट्रंप ने अमेरिकी लोगों को मुश्किल समय के लिये तैयार रहने के लिये कहा है। आशंका है कि इससे भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से एक में मांग कम हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कोई भी अमेरिकी व्यापारिक प्रतिबंध अंततरू भारत के प्रमुख उद्योगों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, हमने उभरते वैश्विक आर्थिक युद्ध से बचने के लिये व्यावहारिक टैरिफ रणनीति को अपनाया है, लेकिन अभी भी बड़े वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका खत्म नहीं हुई है। हालिया केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स में छूट देकर मध्य वर्ग को खुश तो किया है, लेकिन ट्रंप के व्यापार युद्ध की घोषणा से भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

बीमार भविष्य के कारखाने न बनें सरकारी स्कूल

शुभम

यहां सवाल किसी स्कूल की छत ढहने का नहीं है, शिक्षा का सारा ढांचा ही जर्जर है। इस ढांचे की मरम्मत की आवश्यकता है। सरकारी स्कूलों की जगह निजी स्कूलों को बढ़ावा देने की नीति को बदलना होगा, शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। देश में बहुत कुछ हो रहा हैदृ कहीं पुल ढह रहे हैं, कहीं सड़कें नदियां बनी हुई हैं, कहीं विमान– दुर्घटनाएं हो रही हैं, देश का उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे रहा है, संसद में और सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकारी एजेंसियां छापेमारी में लगी हैं। अरबों–खरबों के घोटाले

की बातें हो रही हैं। मतदाता सूचियों को खंगाला जा रहा है। लाखों नाम जुड़ रहे हैं, लाखों काटे जा रहे हैं। नेतागण अपनी–अपनी पार्टी के गुणगान में लगे हैं, कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे किस नेता की बात सच मानें और किसकी झूठ। कहीं भ्रष्टाचार की बात हो रही है, कहीं चुनाव की... इस सारे शोर–शराबे में हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की छत ढह जाने से सात बच्चों की जान चली गय। जो छत गिरी, दो साल पहले ही लगभग तीन लाख रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च होने का दावा किया गया था! शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 'मामले की उच्च स्तरीय जांच' करायेंगे। हकीकत यह है कि देश में सरकारी स्कूल और उनमें दी जा रही शिक्षा दोनों जर्जर अवस्था में हैं। होती है कभी–कभी बात इस जर्जर अवस्था के बारे में, पर अक्सर 'उच्च स्तरीय जांच' की घोषणा ही सुनाई देती है, उसके परिणाम कहीं सरकारी फाइलों में दबे पड़े रहते हैं। इस झालावाड़–कांड की जांच के साथ भी ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सात बच्चों के मरने और चौबीस बच्चों के घायल होने वाले इस हादसे ने देश में सरकारी शिक्षा की स्थिति पर कुछ सवाल जरूर उठायें हैं, पर उनके उत्तर खोजने की बात कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं पूछ रहा कि उन मासूमों का क्या कसूर था, जो खिलने से पहले ही कुम्हला गये? उनके अभिभावकों के सपनों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, इस बारे में कोई बात नहीं हो रही। संसद में 'आपरेशन सिंदूर' के बारे में चर्चा होती रही है। महत्वपूर्ण है यह विषय इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन देश के स्कूलों और शिक्षा की स्थिति की गंभीरता और महत्व को क्यों नहीं समझा जा रहा? झालावाड़ का स्कूल अकेला नहीं है जिसकी इमारत जर्जर अवस्था में है। राजस्थान के ही नहीं देशभर के सरकारी स्कूलों की इमारतें और शिक्षा की स्थिति संसद में काम रोको प्रस्ताव की मांग कर रही है, पर कौन सुन रहा है इस मांग को? देश में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है उसे लेकर विवाद भी उठ रहे हैं। पर यह दुर्भाग्य ही है कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति हमारी वरीयता में कहीं नहीं दिखाई दे रही। शिक्षा का माध्यम क्या हो, कितनी भाषाएं देश के बच्चे सीख रहे हैं जैसे कुछ सवाल यदि कहीं उठ भी रहे हैं तो वह भी अपने–अपने राजनीतिक हितों–स्वार्थों के खातिर ही। शिक्षा को लेकर जो बुनियादी चिंता दिखनी चाहिए, उसमें जो ईमानदारी झलकनी चाहिए, वह कहीं नहीं है। सवाल किसी झालावाड़ के सरकारी स्कूल की छत गिरने का नहीं है, देश के हर हिस्से में ऐसे स्कूल दिख जाएंगे जहां बच्चे दीवारें ढहने या छत गिरने के खतरे को झेलते हुए अपना भविष्य बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आज देश में 74 हजार से अधिक स्कूल जर्जर अवस्था में हैं। आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि देश में सरकारी स्कूल लगातार कम हो रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में पिछले एक दशक में लगभग नब्बे हजार सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। सहज ही विश्वास नहीं होता इस आंकड़े पर, पर शिक्षा को लेकर जिस तरह की अराजकता हमारे देश में पसरी है उसे देखते हुए आश्चर्य भी होना चाहिए और चिंता भी। चिंता इस बात की भी होनी चाहिए कि सरकारी स्कूलों के बंद होने के साथ–साथ निजी स्कूलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ अरसे में 25 हजार से अधिक सरकारी स्कूल बंद हुए हैं! इसका एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर और स्तरीय शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों से निकाल कर अच्छे निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति आयी क्यों? इस सवाल का जवाब भी कोई मुश्किल नहीं हैदृ 'अच्छी शिक्षा' के नाम पर कुकुरमुत्तों की तरह उग रहे निजी स्कूलों को जिस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है उसने शिक्षा को एक व्यवसाय बनाकर रख दिया है। 'इंटरनेशनल स्कूल' कहलाते हैं ये संस्थान! अंग्रेजी माध्यम वाले यह स्कूल पैसे वालों के लिए है और उनके लिए भी जो अपनी जीवन शैली को बेहतर दिखाने की होड़ में लगे हैं। आज एक ओर हमारे देश में झालावाड़ जैसे जर्जर सरकारी स्कूल हैं ।

बलिदान से ज्वाला बनी आजादी की चिंगारी

सुमन

जीवन की तपिश ने क्रांतिकारी उधम सिंह को इतना सशक्त बनाया कि वे लंदन जाकर जलियांवाला कांड के दोषियों को सजा दे सके। उनका सपना देश को गुलामी से मुक्त करना, विवेकशील व सांप्रदायिक सद्भाव से पूर्ण समाज बनाना था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद उधम सिंह का बलिदान अविस्मरणीय है। यह क्रांतिकारी संघर्षमय जीवन व देश के प्रति सर्वस्व समर्पण की मिसाल हैं। उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था। इनका जन्म 26 दिसंबर, 1899 को तत्कालीन पटियाला रियासत के सुनाम कस्बे में हुआ। उधम सिंह के पिताजी का नाम टहल सिंह कंबोज तथा माताजी का नाम नारायणी था। बालक शेर सिंह पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा जब इनकी माताजी का सन् 1901 तथा पिताजी का 1907 में देहांत हो गया। किशन सिंह रागी नामक शख्स ने दोनों भाइयों, शेर सिंह तथा साधू सिंह को सेंट्रल खालसा अनाथालय, अमृतसर में भर्ती कराया। उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार, अनाथालय में 28 अक्तूबर, 1907 को दोनों भाइयों की दीक्षा के बाद शेर सिंह का नाम ऊधम सिंह तथा साधू सिंह का नाम मुक्ता सिंह रखा गया। उधम सिंह ने साल 1918 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अनाथालय छोड़ दिया। वहीं भाई मुक्ता सिंह की मृत्यु के पश्चात इनका जीवन बिल्कुल एकाकी हो गया। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। साल 1918 में उधम सिंह ब्रिटिश सेना में सैनिक के रूप में भी भर्ती हुए और 1919 में भारत वापस लौट आए। दरअसल, बाल्यकाल में माता–पिता व भाई मुक्ता सिंह की मृत्यु, अभावग्रस्त बाल्यकाल, एकाकी जीवन और अनाथालय के जीवन ने उधम सिंह को साहसी, संघर्षशील एवं जुझारू युवक बना दिया। वहीं भारतीय जनता की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय संसाधनों का दोहन, जनता पर अत्याचारों ने भी उनके चिंतन को प्रभावित किया। उनके राजनीतिक चिंतन पर गहरा प्रभाव जलियांवाला बाग नरसंहार (13 अप्रैल, 1919) का पड़ा। इसके अतिरिक्त उन पर क्रांतिकारियों एवं राष्ट्रीय नेताओं, बब्बर अकाली लहर, मार्क्सवाद, लेनिनवाद और विदेश यात्राओं व प्रवास, क्रांतिकारी संगठनों–हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी आदि का प्रभाव पड़ा था। इसी क्रम में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए भारतीयों को संगठित करने हेतु उधम सिंह ने लंदन में 'आजाद पार्टी' का भी गठन किया। शहीद भगत सिंह के व्यक्तित्व, विचारों और कुर्बानी ने उन्हें सर्वाधिक प्रभावित किया। जिन्हें वे 'मित्र' और 'गुरु' मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में उत्पन्न हुई समस्याओं के कारण पंजाब सहित समस्त भारत में जनता में असंतोष चरम पर था। प्रांतीय सरकार ने इसे दबाने के लिए अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 (रोलेट एक्ट) लागू किया। जिसकी भारतीयों ने 'काले कानून' कहकर आलोचना की। इन कानूनों का पंजाब में सर्वाधिक विरोध हुआ। बैसाखी यानी 13 अप्रैल, 1919 को अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण समारोह किया गया। जहां सभी समुदायों के लगभग 20,000 लोग एकत्रित थे। एक साजिश के तहत ब्रिगेडियर जनरल आर.ई.एच. डायर सैनिकों को लेकर शाम 5 बजे सभा स्थल पर आया व बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने के आदेश दिए। सैनिक टुकड़ी ने करीब 1650 गोलियां के साथ फायरिंग की। लगभग 15 मिनट में अमृतसर के सिविल सर्जन डॉ. स्मिथ के अनुसार 1800 स्त्री, पुरुष और बच्चे मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 20वीं शताब्दी में बर्बरता एवं अमानवीयता की मिसाल थी, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ साबित हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उधम सिंह के हृदय में बदला लेने की ज्वाला निरंतर धधकती रही। उन्होंने जनरल डायर से बदला लेने का निर्णय लिया। परंतु डायर साल 1927 में बीमारी से ही मर गया। उधम सिंह ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अनेक छद्म नाम रखे जिनमें उदे, शेर सिंह, उदय, फ्रेंक ब्राजील, उधम सिंह कम्बोज, मोहम्मद सिंह आजाद तथा राम मोहम्मद सिंह आजाद जो सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक हैं। उधम सिंह अपने नाम की भांति एड्रेस भी बदलते रहे। इंग्लैंड प्रवास के दौरान पते में बार–बार परिवर्तन ने पुलिस व गुप्तचर विभाग को भ्रमित किया और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। आम धारणा यह है कि उधम सिंह अविवाहित थे। परंतु उन्होंने दो शादियां की थी। प्रथम विवाह किया अमेरिका प्रवास के दौरान 1923 में लूपे हर्नांडेज से। उधम सिंह ने स्वीकार किया था कि उनके दो बेटे थे। वहीं ब्रिटिश गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट अनुसार, लंदन में नवंबर 1936 में उधम सिंह ने एक श्वेत महिला से शादी की। बता दें कि उधम सिंह साल 1934 में लंदन चले गये। फिर 1940 में जलियांवाला हत्याकांड के 21 वर्ष के बाद उधम सिंह का इंतकाम पूरा होने का वक्त आया। जब लंदन में एक सभा के दौरान माइकल ओ'डायर (1913 से 1919 तक पंजाब के लेफ्टि. गवर्नर) ने अपने भाषण में भारतीयों के लिए अपमानजनक शब्द कहे। वहां मौजूद उधम सिंह ने माइकल ओ'डायर को गोलियां मारी। उसकी मौके पर मौत हो गई। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को माइकल ओ 'डायर की हत्या के जुर्म में पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी। उधम सिंह ने पेंटोविले जेल से 15 जुलाई, 1940 को लिखा कि 'हमारा सबका महान कर्तव्य देश की पुण्य भूमि से अंग्रेजों को बाहर निकालना है।

.... विविध ....

प्रभावी संवाद कला से कैरियर में पायें बढ़त

कंपनियों के लिए अब संवाद कला में माहिर लोग पहली पसंद बन गये हैं, यानी उनकी कम्युनिकेशन इंटेलीजेंस शानदार होती है। ये सहयोगी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। वहीं कर्मियों, मैनेजमेंट व क्लाइंट के बीच बेहतर संबंध स्थापना में मददगार हैं। खुद के कैरियर में भी तरक्की करते हैं। क्लाइंट और कस्टमर के साथ रणनीतिक संवाद में माहिर लोग संगठन के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। तेजी से बदलते कारपोरेट जगत में केवल टेक्निकल स्किल या डिग्री पर्याप्त नहीं मानी जाती। आज कम्युनिकेशन इंटेलीजेंस एक ऐसी दक्षता बनकर उभर रही है, जो किसी भी शैक्षणिक डिग्री से कहीं अधिक प्रभावशाली साबित हो रही है। कंपनियां आज उन प्रोफेशनल्स को ज्यादा तरजीह दे रही हैं, जो न केवल अपनी बात प्रभावी ढंग से कह सकते हैं बल्कि टीम, क्लाइंट, सीनियर्स और कस्टमर के साथ संवेदनशील और रणनीतिक संवाद भी कर सकते हैं। वास्तव में कारपोरेट जगत को यह अहसास हो गया है कि कम्युनिकेशन इंटेलीजेंस केवल बातचीत करने की स्मार्टनेस भर नहीं बल्कि यह सफल रिश्तों, समुचित नेतृत्व और प्रोफेशनल विकास की नींव है। यही कारण है कि अब कंपनियां उन प्रोफेशनल्स को तरजीह दे रही हैं, जो अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कह पाने में सक्षम हैं वहीं क्लाइंट को संतुष्ट करने और कर्मचारियों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में भी माहिर हैं। क्योंकि आज जब दुनिया तेजी से एक–दूसरे से जुड़ रही है या जुड़ चुकी है, तब इंसान की पहचान केवल उसके ज्ञान से नहीं है बल्कि वह संवाद कैसे करता है, इससे भी उसकी पहचान बनती है। यही वजह है कि कारपोरेट जगत में इंट्री के लिए कम्युनिकेशन इंटेलीजेंस का महत्व बहुत बढ़ गया है।

क्लाइंट हैंडलिंग असरदार

कारपोरेट सेक्टर का सीधा वास्ता आज अपने क्लाइंट और कस्टमर से होता है। ऐसे में अगर कोई कर्मचारी ग्राहक की बोलचाल से मनोदशा, उम्मीद और उसकी चिंता का आकलन करके उसे सही प्रतिक्रिया देता है, तो इसमें कंपनी के साथ और रिलेशन तो मजबूत बनते ही हैं, कम्युनिकेशन इंटेलीजेंस का इसमें प्रभावशाली असर साबित होता है। कारपोरेट जगत ऐसे लोगों को अपने यहां ज्यादा जगह दे रहा है, जो अच्छे नेता के साथ साथ अच्छे वक्ता भी हैं यानी अपनी बात स्पष्ट, प्रेरक और संतुलित ढंग से रख पाते हैं।

टीम वर्क के लिए उपयोगी स्किल

एक अच्छा टीम लीडर वही हो सकता है, जो अपने साथियों को अपने प्रभावशाली संवाद करने के अंदाज में उनसे अपनी बात मनवा ले। आजकल किसी भी टीम को अपना ऐसा लीडर नहीं चाहिए, जो उनमें अपना बॉसिज्म झाड़े बल्कि ऐसा सहकर्मी चाहिए होता है, जो अपने टीम के सदस्यों को समझे और उन्हें आपस में एकजुट बनाये रखने के लिए सकारात्मक रुख अपनाए। टीम का मनोबल, तालमेल और प्रदर्शन किसी हद तक टीम लीडर के व्यवहार और उसके सक्षम संवाद कला पर निर्भर होता है। कारपोरेट लीडर के लिए संवाद कला आनी जरूरी हो गई है।

विवाद समाधान में मददगार

जो व्यक्ति अच्छे से बात कर सकता है, वह किसी भी स्थिति में किसी को अपनी बात सहजता से समझा सकता है। कारपोरेट वातावरण में रोजमर्रा के कामकाज के दौरान अनेक जगहों पर मतभेद, दबाव और असहमति की स्थिति से सामना होना आम बात है। ऐसी जगहों में वो लोग बड़े काम के साबित होते हैं, जो बातचीत करने के तरीके में माहिर होते हैं। कम्युनिकेशन इंटेलीजेंस वाले लोग बात को समझकर सही शब्दों और सही टोन में समाधान निकालने की कला जानते हैं।

ब्रांड इमेज और प्रेजेंटेशन

कारपोरेट जगत में कोई प्रोफेशनल अपने आपमें कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं होता, वह जिस कंपनी या जिस उद्योग समूह के साथ जुड़ा होता है, उसी का एक जरूरी चेहरा होता है। इसलिए कारपोरेट प्रोफेशनल हर पल अपनी कंपनी के प्रतिनिधि चेहरा होते हैं और अपनी कंपनी या समूह के अंबेसडर भी होते हैं। ऐसे में अगर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इंटेलीजेंस में माहिर हैं तो उसकी बातचीत के ढंग से, प्रेजेंटेशन से और क्लाइंट डील की शैली से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ।

कंपनी कल्चर को सशक्त बनाते हैं

जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इंटेलीजेंस से लैस होते हैं, ऐसे लोग सिर्फ अपना ही रुतबा नहीं बनाते बल्कि कंपनी के कामकाजी वातावरण को भी शानदार कल्चर में बदल देते हैं। ऐसे लोग खुले विचारों के, व्यवहार में पारदर्शी और सहयोगी कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण कंपनी में सकारात्मक वातावरण तैयार होता है। कम्युनिकेशन इंटेलीजेंस में माहिर प्रोफेशनल कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच एक ऐसी सकारात्मक संवाद कड़ी बन जाते हैं कि दोनों तरफ से जब भी कोई अड़चन आती है या कहीं कोई फसाहट होती है, तो ऐसे प्रोफेशनल ऐसी समस्याओं का चुटकी बजाते हल निकाल लेते हैं। इससे कंपनी का माहौल पॉजीटिव और प्रोडक्टिव बनता है।

गेम चेंजर निगोशिएटर

कम्युनिकेशन इंटेलीजेंस में माहिर लोग गजब के डील मेकर होते हैं। निगोशिएसन टेबल पर हमेशा बाजी इनके हाथ लगती है, क्योंकि गेमचेंजर निगोशिएटर होते हैं। दरअसल कोई भी सौदा महज छोटी बड़ी धनराशि का आधार नहीं होता बल्कि सौदे के संवाद का सुखद नतीजा होता है। ऐसे व्यक्ति कभी शब्दों का बिखेरकर तो कभी चुप रहकर ही अपने पक्ष में बाजी पलट लेते हैं। कम्युनिकेशन इंटेलीजेंस में दक्षता या कौशल का कंपनी को भरपूर फायदा होता है और इस कारण ये कंपनी की आंख के तारे बनते हैं।

मेंटल हेल्थ व वेलनेस क्षेत्र में उम्मीदों का पेशा

कई वजहों से देश में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की मांग बढ़ी है। यह सेक्टर तेज विकास कर रहा है। शिक्षा, कारपोरेट, स्पोर्ट्स, जेल और सेना में मेंटल हेल्थ पेशेवरों की जरूरत है। एमए या एमएससी मनोविज्ञान के बाद क्लीनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी या वेलनेस कोचिंग फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। भारत में हर आठ में से एक व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से घिरा हुआ है दृ यह तथ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2024 की एक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट में सामने आया है। इसलिए भारत में मेंटल हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। आज शिक्षा, कारपोरेट, स्पोर्ट्स, जेल, सोशल सेक्टर और मिलिट्री यानी भारतीय सेनाओं आदि सभी जगहों पर एक मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल की जरूरत है। देश में कई ऐसी योजनाएं भी चला रखी हैं, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नियुक्ति होती है। जैसे– नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और मनोदर्पण (विद्यार्थियों के लिए)। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विशेषज्ञों की मांग के कारण आज मेंटल हेल्थ और वेलनेस सेक्टर में सालाना 15 से 20 फीसदी की वृद्धि दर जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि दर अगले कई सालों तक बरकरार रहेगी। साल 2025 में जहां भारत में 1 लाख साइकोलॉजी और काउंसलिंग प्रोफेशनल्स की जरूरत है।

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

यह क्षेत्र कितनी तेजी से शानदार कैरियर का उभरता हुआ क्षेत्र बन गया है। सवाल है इस सेक्टर में कैरियर बनाने के लिए न्यूनतम क्वॉलीफिकेशन क्या है? तो अगर आपको काउंसलिंग प्रोफेशनल्स बनने की दिशा में आगे बढ़ना है, तो आपको बीए या बीएससी साइकोलॉजी में होना जरूरी है। इसके बाद पीजी प्रोग्राम करने के लिए एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी होना जरूरी है। तभी क्लीनिकल साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी में कैरियर बना सकते हैं। अगर पीजी के बाद का कैरियर बनाना है तो एमफिल इन क्लीनिकल साइकोलॉजी (आरसीआई–अप्रूव्ड) कोर्स आप पीजी के बाद कर सकते हैं और अगर थैरेपी और वेलनेस कोचिंग में कैरियर बनाना है, तो किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएट होने के बाद आपको

सर्टिफिकेट या डिप्लोमा काउंसलिंगः आर्ट थैरेपी में लेना होगा। वेलनेस कोचिंग के लिए भी यही न्यूनतम शैक्षिक जरूरत है।

प्रमुख कोर्स और स्पेशलाइजेशन

क्लीनिकल साइकोलॉजी– मानसिक रोगों की पहचान, परीक्षण और उनकी चिकित्सा के लिए यह स्पेशलाइजेशन जरूरी है।

काउंसलिंग साइकोलॉजी– रिश्ते, तनाव, छात्रों की परेशानियों, पारिवारिक समस्याओं आदि की काउंसलिंग करने के लिए काउंसलिंग साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन जरूरी है। चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकोलॉजी– बच्चों और किशोरों की मानसिक समस्याओं का इलाज करने के लिए इस विषय में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी– दिव्यांगों या मानसिक रोगियों के पुनर्वास में मदद आदि के लिए रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन जरूरी है। वेलनेस कोचिंगः होलिस्टिक साइकोलॉजी– योग, मेडीटेशन, जीवनशैली और संतुलन की काउंसलिंग के लिए यह विशेषज्ञता चाहिये।

पढ़ाई के लिए प्रमुख संस्थान

निमहांस, बेंगलुरु– यहां से आप आरसीआई अप्रूव्ड एम.फिल. इन क्लीनिकल साइकोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। टिस, मुंबई– यहां से काउंसलिंग स्पेशलाइजेशन के लिए एमए इन अप्लाइड साइकोलॉजी की डिग्री ले सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय– यहां से एमए साइकोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली– यहां से क्लीनिकल साइकोलॉजी की पढ़ाई की जा सकती है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु– यहां से बीए और एमसी इन साइकोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं। अबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली– यहां से आप एमए साइकोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं। इग्नू– यहां से पीजी डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग विषय की पढ़ाई कर सकते हैं।

जरूरी स्किल्स

मेंटल हेल्थ और वेलनेस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए उम्मीदवार में कुछ पेशेवर कौशल होने जरूरी हैं। मसलन, इम्पैथी और लिसनिंग स्किल, इमोशनल इंटेलीजेंस, इथिक्स एंड कॉन्फिडेंटलिटी, डायग्नोस्टिक टेक्निक, बेसिक न्यूरो साइंस अंडरस्टैंडिंग, काउंसलिंग टेक्निक (सीबीटी, आईबीटी, टॉक थैरेपी)।

जॉब प्रोफाइल

क्लीनिकल साइक्लॉजिस्ट– हॉस्पिटल, मानसिक संस्थान में कार्यरत होता है। काउंसलर (स्कूल, कैरियर, मैरिज)– स्कूल, एनजीओ या फिर प्राइवेट क्लीनिक में काउंसलर की जॉब होती है। वेलनेस कोच– फिटनेस सेंटर और कारपोरेट ऑफिस में इनकी नियुक्ति होती है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर– इनकी नियुक्ति सरकारी संस्थानों, जेल और पुनर्वास केंद्र में होती है।

पुलिस भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू

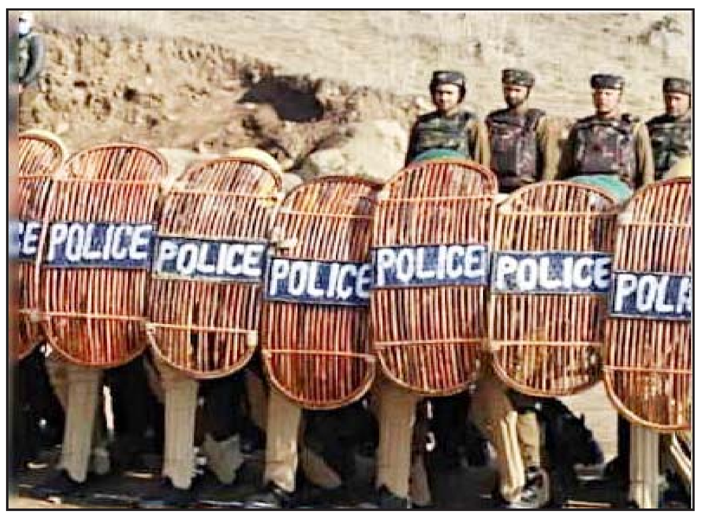

लखनऊ, (संवाददाता)। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सभी विज्ञापित किए जाने वाले पदों के आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) प्रणाली बृहस्पतिवार से लागू कर दी गई है। यह प्रक्रिया विभिन्न भर्तियों को पारदर्शिता एवं शुचितापूर्ण तरीके से सम्पन्न कराये जाने एवं आवेदन प्रक्रिया को सुगम एवं सुविधाजनक बनाये जाने हेतु अपनाई जा रही है। भर्ती बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक, अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट नचचइचइ.हवअ.पद पर जाकर दिए गए लिंक पर वांछित सूचनाएं भरकर ओटीआर की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ओटीआर पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए त्वरित पूछे जाने वाले सवाल व वीडियो का लिंक भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। यदि अभ्यर्थियों को पंजीकरण करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो वह हेल्पलाइन नंबर– 1800 9110 005 पर सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।

अक्टूबर में होगी कंप्यूटर ऑपरेटर सीधी भर्ती की परीक्षा

वहीं दूसरी ओर बोर्ड ने सूचित किया है कि पुलिस में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–ए के पदों पर सीधी भर्ती– 2023 तथा उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती– 2023 की लिखित परीक्षा अक्टूबर माह में कराया जाना प्रस्तावित है।

खत्म हुआ मौखिक आदेश का दौर अब होंगे लिखित आदेश : मंत्री एके शर्मा

लखनऊ, (संवाददाता)। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को पॉवर कॉर्पोरेशन और निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय है, अब कार्रवाई की जाएगी। कॉर्पोरेशन और निगमों को चेताया कि बार–बार मौखिक आदेश दिए गए हैं। अब लिखित में आदेश दिए जाएंगे। उन्होंने एक पत्र के जरिये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान भी दिलाया है। कहा कि छोटे–छोटे बकाया होने पर और उपभोक्ता द्वारा तुरंत बिल जमा करने की तैयारी बताने पर भी कनेक्शन काट दिया जा रहा है। ऐसा करने वाले बिजलीकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह कुछ लोगों का बिल बकाया होने पर पूरे फीडर या गांव की लाइन काट दी जाती है। यह गलत है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बिंदुओं पर भी ध्यान देने के निर्देश ऐसे फीडर पर जला हुआ ट्रांसफार्मर नहीं बदलना या उच्चीकरण नहीं करना भी न्यायसंगत नहीं है। ट्रांसफार्मर बदलना और राजस्व वसूल करना दोनों प्रक्रिया अलग–अलग की जाएं। – कई बार फीडरध्ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने और बार–बार बिजली ट्रिप होने या लो वोल्टेज होने के बावजूद ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण क्यों नहीं किया जाता। बिजली चोरी रोकना हमारी प्राथमिकता है लेकिन उसके लिए अलग कार्रवाई की जाए। चोरी रोकने के लिए बिजली ही रोक देने की बात उचित नहीं है। ट्रांसफार्मर जलने के बाद कई दिन तक रिपोर्ट नहीं होता। ट्रांसफार्मर की उपलब्धि से लेकर उसे लगाने में देरी के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। गलत बिल की शिकायते विशेष चिंता का विषय है। इसके साथ कुछ कर्मियों के भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आती रहती हैं। इसपर विराम लगे। मेंटेनेंस कार्य करना आवश्यक हो तो सामान्य रोस्टिंग के समय किया जाय। लोगों को पूर्व जानकारी देकर ही शटडाउन लिया जाय। कुशल व काम करने वाले संविदाकर्मियों की बड़ी संख्या को हाल में निकाल दिया गया है। उनकी जगह पर अकुशल कर्मी रखे गए हैं। इसकी समीक्षा कर दोषियों पर कार्रवाई करें। 1912 टोल फ्री नंबर की व्यवस्था को तुरंत ठीक करें। अधिकारी फरियादियों का फोन उठाने की आदत डालें। शिकायतों के निस्तारण के लिए यूपीपीसीएल और डिस्कॉम के स्तर पर भी निदेशक स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी तीन शिफ्ट में लगाई जाए। विजिलेंस की टीम कुछ स्थानों में हो रही बड़ी और संगठित चोरी पर ही ध्यान केंद्रित करे।

संक्षिप्त खबरें

पुरानी पेंशन के लिए अटेवा का रोष मार्च ,सरकार ने मागे नहीं मानी तो 1 अक्टूबर को डेल्ही में करेंगे घेराव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। अटेवा पेंशन बचाओ मंच जौनपुर ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आवाह्न पर 1 अगस्त शुक्रवार को को छच्ै६ न्चै के विरोध में रोष मार्च निकाला । रोष मार्च का आयोजन अम्बेडकर तिराहा से जोगियापुर, ओलंदगंज , जेसीज चौराहा , रोडवेज , विकास भवन होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन के साथ संपन्न हुआ। रोष मार्च में जनपद के समस्त शिक्षक, कर्मचारी सम्मिलित हुए साथ ही साथ विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। रोष मार्च को जनपद के सभी विभागों और संगठनों ने न केवल अपना समर्थन दिया बल्कि अपनी एवं अपने पदाधिकारियों के साथ रोष मार्च में भौतिक रूप से उपस्थिति भी दर्ज कराई । इस अवसर पर अटेवा मण्डल उपाध्यक्ष रमेश चन्द्र यादव ने कहा कि अटेवा छच्ै६ न्चै का पूर्ण बहिष्कार करता है और उन्होंने आवाह्न करते हुए नारा दिया रू– एक युद्ध – निजीकरण के विरुद्ध। माण्डलिय महामन्त्री सन्दीप चौधरी ने कहा कि पेंशन कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है कोई भीख नही। प्रान्तीय सह संयोजक डॉ यामिनी सिंह ने कहा कि निजीकरण के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। जिला संयोजक चन्दन सिंह एवं जिला महामंत्री इन्दु प्रकाश यादव ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है।यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 1 अक्टूबर को। गांधी जयंती के पूर्व संध्या पर दिल्ली के राम लीला मैदान में सरकार का पूरे देश के शिक्षक घेराव करेंगे।जिला कोषाध्यक्ष नन्द लाल पुष्पक ने अपने संबोधन में कहा कि छच्ै और निजीकरण किसी भी रूप में देश और लोक कल्याण के लिए हितकर नही है। जिला कैडर प्रभारी टी यन यादव, जिला संयोजक महिला विंग आराधना चौहान, जिला कैडर सह प्रभारी द्वय जगदीश यादव, प्रदीप चौहान, जिला संगठन मंत्री त्रय अरविंद यादव, सुभाष सरोज, सन्दीप यादव , श्याम सुंदर उपाध्याय, शांत सिंह, रोहित सिंह, मिथिलेश कुमार, एवं सभी जनपदीय पदाधिकारी ,विभिन्न ब्लॉकों के अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी सम्मिलित हुए। पेंशन आंदोलन को सम्बल प्रदान करने के लिए विभिन्न संगठनों ने भी अपना समर्थन देने के लिए उपस्थित रहे।

विलय वाले प्राथमिक स्कूल के शिक्षक कर सकेंगे समायोजन का आवेदन

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के लिए चल रही समायोजन व तबादला प्रक्रिया में विलय होने वाले विद्यालयों के शिक्षकों को भी आवेदन करना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इसके लिए बुधवार को संशोधित आदेश जारी किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे विद्यालय जो किसी विद्यालय में विलय (पेयरिंग) हुए हैं, में कार्यरत सभी शिक्षकों द्वारा पोर्टल पर दिख रहे शिक्षकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों (डेफसिट) में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हालांकि इस आदेश को लेकर शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति है। उनका कहना है कि विलय वाले विद्यालय के शिक्षक वर्तमान में आधिकारिक रूप से कहां पर तैनात हैं? अगर वह विलय किए गए विद्यालय में तैनात हैं तो फिर शिक्षक–छात्र अनुपात के आधार पर उनकी गणना सरप्लस व आवश्यकता वाले विद्यालयों के रूप में की गई होगी। क्या उन्हें जिस विद्यालय में उनका विलय हुआ है, वहां के लिए भी आवेदन करना होगा? हालांकि विभाग के अधिकारी इस पर मौन साधे हुए हैं। जानकारी के अनुसार काफी ऊहापोह व तकनीकी दिक्कत की वजह से इस बार काफी कम आवेदन हो रहे हैं।

शिक्षक–कर्मचारियों को फॉर्म 16 उपलब्ध कराने के निर्देश

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को फार्म 16 निरूशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

परिजनों को भी नहीं पता, राजकुमार के पास कहां से आया रिवॉल्वर

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश चकबंदी निदेशालय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष व चकबंदी मुख्यालय में तैनात बाबू आशियाना सेक्टर–जे निवासी राजकुमार सिंह (52) की मौत के मामले में पुलिस को सबसे पहली सूचना उनके कार चालक ने दी। चालक की सूचना पर परिजन भी शहीद पथ स्थित उनके प्लॉट पर पहुंचे। प्लॉट में बने कमरे के अंदर उनका शव पड़ा था। उनके सिर में गोली लगी थी और दाहिने हाथ में रिवॉल्वर था। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया राजकुमार सिंह की मौत आत्महत्या लग रही है। उनके पास से एफएसएल टीम को सुसाइड नोट मिला है। नोट में उन्होंने खुद को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। उनके पास से मिली रिवॉल्वर लाइसेंसी लगी रही है। एफएसएल टीम ने रिवाल्वर व सुसाइड नोट को जांच के लिए भेजा है। उधर, परिजनों का कहना है कि राजकुमार सिंह के पास लाइसेंसी असलहा नहीं था। उसके पास रिवॉल्वर कहां से आया, किसी को कुछ नहीं पता।

ज्योतिष के ज्ञाता थे राजकुमार सिंह

राजकुमार सिंह पूर्व सांसद धनंजय सिंह व पूर्व राज्यमंत्री राणा अजीत सिंह के करीबी भी थे। घटना की जानकारी पर ये दोनों भी मौके पर पहुंचे। लोगों ने बताया कि राजकुमार सिंह ज्योतिष के ज्ञाता थे। अधिकारियों से लेकर राजनेता तक उनकी राय लेकर काम करते थे। परिजन व उनके परिचितों का कहना है कि राजकुमार सिंह आत्महत्या नहीं कर सकते हैं।

संक्षिप्त खबरें

चालक को झपकी आने से खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, एक की मौत व चार घायल

लखनऊ, (संवाददाता)। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अयोध्या जिले के कुमारगंज थाना क्षेत्र के दहपेल का पुरवा मजरे गुमानीगंज के पास एक बड़ा हादसा हो गया। कार चालक को बृहस्पतिवार की सुबह करीब साढ़े पांच बजे झपकी आने के कारण कार खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही यूपीडा के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को यूपीडा की एंबुलेंस से सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय कुमारगंज पहुंचाया। जहां चिकित्सक डॉ. अरविंद मौर्या और डॉ. प्रशांत वर्मा ने 56 वर्षीय भीष्म सिंह को मृत घोषित कर दिया। अन्य चार घायलों को गंभीर चोटें आने के कारण मेडिकल कॉलेज अयोध्या रेफर किया गया है। चिकित्सक ने बताया जिसमें से सभी को हेड इंजरी भी है यहां इलाज होना संभव नहीं था जिसके चलते प्राथमिक उपचार कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार भीष्म सिंह पुत्र बलजीत सिंह (26 वर्ष), किरन सिंह पत्नी भीष्म सिंह (40 वर्ष), श्रेया सिंह पुत्री भीष्म सिंह (24 वर्ष), अंकित सिंह पुत्र शिव कुमार सिंह (32 वर्ष) निवासी जनपद बलिया और सुमन सिंह पत्नी सत्येंद्र बहादुर सिंह (60 वर्ष) गाजीपुर कार में सवार होकर लखनऊ से बलिया जा रहे थे तभी यहां हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने पर थाना कुमारगंज पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे की जानकारी पीड़ित परिवार के सदस्य को दी गई है।

कृषि यंत्रीकरण योजनाओं से जुड़ें किसान, अनुदान का लाभ पाने के लिए बरतें यह सावधानियां

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम प्रदेश के किसानों के लिए एक लाभकारी व कृषकदृकेंद्रित योजना है। इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से कम लागत, कम समय में अधिक उपज प्राप्त करने में मदद करना है। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू जैसी योजनाएं चलाई हैं, जिनमें किसानों को सत्यापन के बाद आधुनिक कृषि यंत्रों पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से अनुदान दिया जाता है।विशेषज्ञों के अनुसार, इन योजनाओं का लाभ केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही लिया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान योजना की संपूर्ण प्रक्रिया और उससे जुड़ी सावधानियों की जानकारी रखें, जिससे उन्हें अनुदान प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न होवर्तमान में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा यंत्रों की बुकिंग की गई है, जिसकी टोकन कन्फर्मेशन प्रक्रिया ई–लॉटरी के माध्यम से की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसान केवल उन्हीं फर्मों से कृषि यंत्र खरीदें जो पोर्टल पर पंजीकृत हैं। किसी भी अनधिकृत फर्म, निर्माता, डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से खरीदे गए यंत्रों पर अनुदान नहीं दिया जाएगा।कृषकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यंत्र क्रय करते समय फर्म उनके पंजीकरण नंबर, आधार नंबर, टोकन नंबर, नाम व गांव संबंधी विवरण पोर्टल पर फीड करें।

हिन्दी संस्थान में गोस्वामी तुलसीदास, प्रेमचन्द, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी और गुलेरी जी की स्मृति में संगोष्ठी सम्पन्न

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की ओर से हिन्दी भवन के निराला सभागार में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन बुधवार को किया गया। यह संगोष्ठी गोस्वामी तुलसीदास, संत साहित्य मर्मज्ञ आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द एवं कथा सम्राट चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की स्मृति को समर्पित रही।इस अवसर पर डॉ. हरिशंकर मिश्र, असित चतुर्वेदी, नरेन्द्र भूषण एवं डॉ. अलका पाण्डेय का स्वागत उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की प्रधान सम्पादक डॉ. अमिता दुबे द्वारा स्मृति चिह्न भेंट कर किया गया।अपने वक्तव्य में डॉ. हरिशंकर मिश्र ने गोस्वामी तुलसीदास को लोकहितकारी साहित्यकार बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को जनसेवा और धर्म के लिए समर्पित किया। उनके काव्य में गंगा जैसी पवित्रता और सबके कल्याण की भावना समाहित है। उन्होंने संत के लक्षणों की स्पष्ट व्याख्या की और कहा कि केवल वस्त्र व वाणी से नहीं, बल्कि स्वभाव से जो संत हो वही सच्चा संत होता है।वरिष्ठ साहित्यकार असित चतुर्वेदी ने संत साहित्य पर प्रकाश डालते हुए आचार्य परशुराम चतुर्वेदी की संत परम्परा में की गई साधना और शोध को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि परशुराम चतुर्वेदी पेशे से वकील होने के बावजूद साहित्य–साधना में पूरी तरह रमे रहे। उनकी पुस्तक 'उत्तरी भारत की संत परम्परा' संत साहित्य में शोध की आधारशिला है।नरेन्द्र भूषण ने प्रेमचन्द के रचनात्मक अवदान को स्मरण करते हुए कहा कि उनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने समय में था। 'गोदान', 'गबन', 'कायाकल्प', 'रंगभूमि' जैसी रचनाएँ सामाजिक यथार्थ और आदर्श का अनूठा संगम हैं। उन्होंने बताया कि प्रेमचन्द का साहित्य देशभक्ति, सामाजिक बदलाव और मानवीय संवेदना का प्रतीक है।डॉ. अलका पाण्डेय ने चन्द्रधर शर्मा गुलेरी के साहित्य पर चर्चा करते हुए कहा कि उनकी कहानियाँ प्रेम और आंचलिकता की बारीक बुनावट से भरी हैं। उन्होंने कहानी विधा को दिशा दी। 'उसने कहा था' जैसी रचना उन्हें अमर साहित्यकारों की श्रेणी में स्थापित करती है।कार्यक्रम में संगीत कला संस्थान द्वारा गोस्वामी तुलसीदास के पदों जैसे 'श्रीरामचंद्र कृपालु भजमन', 'गाइये गणपति जगवंदन', 'ठुमक चलत रामचंद्र' आदि की संगीतमय प्रस्तुति दी गई। इसमें डॉ. पूनम श्रीवास्तव ने स्वर दिए, जबकि तबले पर डॉ. राजीव शुक्ला, हारमोनियम पर चन्द्रेश पाण्डे और बांसुरी पर दीपेन्द्र कुमार ने संगति की।संगोष्ठी का संचालन करते हुए डॉ. अमिता दुबे ने सभी वक्ताओं, साहित्यकारों, विद्वानों और मीडिया कर्मियों का आभार प्रकट किया। समारोह में अनेक साहित्यप्रेमी, शोधार्थी और संस्कृतिकर्मी उपस्थित रहे।

छात्रों के नवाचारी विचारों के लिए इंस्पायर-मानक योजना में नामांकन शुरू

लखनऊ, (संवाददाता)। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान–भारत द्वारा संचालित इंस्पायर–मानक योजना के अंतर्गत वर्ष 2025–26 के लिए उत्तर प्रदेश सहित देशभर के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों से नवाचारी एवं मौलिक विचारों के ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। नामांकन की प्रक्रिया 15 जून 2025 से प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक छात्र–छात्राएं योजना की आधिकारिक वेबसाइट पदेचपतमूंतके–केज.हवअ.पद पर जाकर अपने विचार अपलोड कर सकते हैं।माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेन्द्र देव ने प्रदेश के सभी मंडलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा परिषद, संस्कृत शिक्षा परिषद, सीबीएसई एवं सीआईएससीई से संबद्ध विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से प्रत्येक विद्यालय से पांच श्रेष्ठ विचारों का नामांकन सुनिश्चित कराएं। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला, विकासखंड व विद्यालय स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के मध्य समन्वय एवं अनुश्रवण को मजबूत किया गया है।विद्यालयों से अपेक्षा की गई है कि वे पोर्टल पर उपलब्ध अभिनव कहानियाँ छात्रों को पढ़वाएं और शिक्षकों को शिक्षक पुस्तिका का अध्यापन कराएं, ताकि छात्र अपने स्वयं के मौलिक विचारों को बेहतर ढंग से विकसित कर ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकें।उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा विवेक नौटियाल ने बताया कि इस वर्ष से कक्षा 11 और 12 के विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं को भी योजना में शामिल किया गया है। प्रत्येक विद्यालय अधिकतम पाँच विचारों का नामांकन कर सकता है, जिनमें से अधिकतम दो विचार कक्षा 11–12 (विज्ञान वर्ग) के हो सकते हैं।पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश ने 2,10,347 नामांकन कर देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, साथ ही देश के शीर्ष 50 जनपदों में उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों को स्थान मिला था। योजना का उद्देश्य छात्रों में नवाचार, रचनात्मकता, सामाजिक आवश्यकता के समाधान और पर्यावरण मित्रता जैसे विचारों को प्रोत्साहित करना है।योजना के अंतर्गत चयनित श्रेष्ठ विचारों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संबंधित छात्र–छात्रा के बैंक खाते में 10,000 रुपये की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (क्ठज) के माध्यम से दी जाएगी। इसके बाद विद्यार्थी अपने विचार पर आधारित मॉडल या प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, जिसे जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली इंस्पायर मानक प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया जाएगा।

लखनऊ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अहम बैठक

लखनऊ, (संवाददाता)। भारत सरकार के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में बुधवार को राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में एक महत्वपूर्ण प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर के नेतृत्व में हुई इस बैठक में आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल, सचिव मीता राजीव लोचन और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप, प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा, प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा और निदेशक डॉ. वंदना वर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित कर पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़ी नीतियों, योजनाओं और उनकी प्रगति की समीक्षा करना रहा। बैठक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन, कार्यप्रणाली और अब तक की उपलब्धियों का परिचय प्रस्तुत किया गया। आयोग द्वारा जातीय पहचान, जातियों की सूची के अद्यतन, सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण, शिकायत निवारण और नीतिगत अनुसंधान जैसे कार्यों की जानकारी दी गई। संगठनात्मक ढांचे, स्वीकृत–रिक्त पदों, उपलब्ध मानव संसाधन और बजट प्रावधानों की विस्तार से समीक्षा की गई।बैठक में उत्तर प्रदेश के उन पिछड़े वर्गों का विवरण प्रस्तुत किया गया जिन्हें अब तक केंद्र की सूची में शामिल नहीं किया जा सका है। आयोग ने इन जातियोंध उपजातियोंध्उपनामों को केंद्रीय सूची में शामिल कराए जाने की प्रक्रिया पर राज्य सरकार के साथ विचार–विमर्श किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सामाजिक–आर्थिक अध्ययनों और क्षेत्रीय जनसुनवाइयों की रिपोर्टों को भी साझा किया गया, जिन्हें केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले संस्तुतियों का आधार बनाया जाएगा।राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने राष्ट्रीय आयोग से अनुरोध किया कि वे राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केंद्रीय सूची में लंबित जातियों को शीघ्र शामिल कराने की संस्तुति केंद्र को भेजें। प्रदेश आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने राज्य स्तर पर जारी सर्वेक्षणों और सार्वजनिक संवादों का हवाला देते हुए बताया कि व्यापक तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर काम किया जा रहा है और इनका बेहतर समन्वय केंद्र के साथ होना चाहिएबैठक के समापन पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योजनाएं और मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय हैं। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि आयोग राज्य से प्राप्त सभी सुझावों को संज्ञान में लेकर उन्हें भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा और त्वरित क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संस्तुतियाँ देगायह बैठक राज्य और केंद्र के बीच पिछड़ा वर्ग कल्याण की दिशा में ठोस और समन्वित प्रयासों को गति देने की दृष्टि से बेहद अहम रही, जिससे आने वाले समय में नीतिगत निर्णयों और जातीय प्रतिनिधित्व की दिशा में नए मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।

विरोध में उतरे छात्र, फीस बढ़ाने का फैसला वापस

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रावासों की फीस बढ़ाने के विरोध में छात्रों ने बुधवार को हंगामा किया। विवि प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया चल रही है और बीच में ही दो हजार रुपये शुल्क बढ़ा दिया गया है। छात्र अधिष्ठाता कल्याण के कार्यालय का भी घेराव किया गया। विरोध को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन बैकफुट पर आया और फीस बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया गया। हालांकि, अधिकारियों ने पहले ही फीस बढ़ाने की बात से इनकार किया है। छात्रों के समर्थन में उतरे समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों ने कहा कि छात्रावास की फीस सीधे दो हजार रुपये बढ़ाना उचित नहीं है। यह विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी है। मौके पर छात्र सभा इकाई अध्यक्ष प्रिंस कुमार, लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव व शोध छात्र अभिषेक श्रीवास्तव थे। प्रदेश सचिव छात्र सभा अक्षय यादव, सतीश चंद्र, अविनाश यादव, आदित्य पांडेय, रोहित यादव, शिवा जी यादव, धर्मेंद्र, नीतीश, अनमोल राय, रुद्रवीर, प्रभात, शिव पूजन आदि भी प्रदर्शन में शामिल रहे। एनएसयूआई के सदस्यों ने निकाली रैली छात्र संगठन एनएसयूआई ने लविवि के छात्रावास में मेस की कॉशन फीस के नाम पर अधिक शुल्क का आरोप लगाया। इस दौरान साइकिल यात्रा भी निकाली गई।

'नवनियुक्त एसडीएम ने संभाला कार्यभार,पीड़ित को न्याय दिलाना पहली प्राथमिकता'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली–(हरदोई)' तहसील सवायजपुर के नवागत एसडीएम हरियाणा राज्य के जनपद करनाल निवासी मयंक कुंडू ने बुधवार को तहसील पहुँच कर पद भार ग्रहण कर लिया। तहसील के कार्यभार संभालने के बाद एसडीएम ने तहसील परिसर का गहनता से निरीक्षण करते हुए कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित एवं निर्दोष व्यक्ति की हर संभव मदद की जायेगी पीड़ित व्यक्ति के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आपको बता दें कि नवनियुक्त एसडीएम मयंक कुंडू (पीसीएस) ने उत्तरप्रदेश 2023 पीसीएस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में 15वीं रैंक प्राप्त कर जनपद बिजनौर में 10 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत शासन द्वारा उन्हें प्रारंभिक नियुक्ति जनपद हरदोई की तहसील सवायजपुर में उपजिलाधिकारी के पद पर मिली है। जिसके बाद नवनियुक्त एसडीएम ने तहसील मुख्यालय पहुँच कर कार्यभार ग्रहण कर लिया। शुक्रवार को पत्रकार जनार्दन श्रीवास्तव सहित अन्य पत्रकारों ने नवनियुक्त एसडीएम से अनौपचारिक रूप से भेंट की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वह शासन की मंशानुरूप प्रतिदिन कार्यालय में बैठकर जन समस्याओं को सुनेंगे।नवनियुक्त एसडीएम एक युवा और तेजतर्रार प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति से तहसील क्षेत्र वासियों में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और पारदर्शिता की उम्मीदों के साथ ही क्षेत्र में विकास कार्यों में गति आएगी। नवागत एसडीएम की कुशल कार्यशैली और त्वरित निर्णय क्षमता को देखते हुए जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण की पीड़ितों में उम्मीद की किरण जागी है। एसडीएम ने कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी कि पीड़ित व्यक्ति को उनके यहाँ से न्याय मिल सके और कोई फरियादी निराश होकर न लौटे। उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि जाएगी और कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों पर शख्त कार्यवाही की जाएगी और सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। इसके लिए राजस्व की टीम गठित कर अभियान चलाया जाएगा। एक सवाल के जबाव में उन्होंने बताया कि शासन की प्राथमिकताओं का शत प्रतिशत पालन कराना प्रथम कर्तव्य होगा और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन– जन तक पहुँचाना और कार्यक्रमों को प्राथमिकता से किर्यान्वित कराना मुख्य उद्देश्य होगा।

टीकाकरण को लेकर धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक संपन्न

अयोध्या। शुक्रवार को भरत कुंड भदरसा के अंतर्गत मदरसा जामिया अरबिया बहरुल उलूम में धार्मिक गुरुओं के साथ नियमित टीकाकरण ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस में सहयोग टीकाकरण से इनकार परिवारों को घर–घर परामर्श मस्जिद से टीकाकरण के लिए इमाम द्वारा टीकाकरण को लेकर चर्चा किया गया।अनौपचारिक चर्चा की शुरुआत ब्लॉक मोबिलाइज कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ धीरेंद्र नाथ पांडे द्वारा मदरसा के प्रिंसिपल मुफ्ती हसनैन और प्रबंधक ताजमहल अहमद के साथ बैठक किया।बैठक में धीरेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि मदरसे पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेगा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है साथ ही साथ 18 वार्डों में पैदाइशी से 5 साल 10 साल और 16 साल के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के तक के लिए कैंप लगाया

गया है।सभी तरह की जांच मेगा कैंप में किया जा रहा है नियमित टीकाकरण के अंतर्गत बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाव ठीक है लगाए जा रहे हैं।जिनमें टीवी रोग, पल्स पोलियो, गला घोटू,काली खांसी, टेटनेस, पीलिया, निमोनिया, खसरा, रूबेला, दिमाग की बुखार और दस्त प्रबंधन यह सभी में लगाए जा रहे हैं।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसौधा के अधीक्षक डॉ. प्रदीप कुमार द्वारा मदरसे से सहयोग की अपील किया गया और मदरसे में पढ़ने वाले 10 साल और 16 साल के सभी बच्चों को टीका लगवाने में सहयोग करने के लिए अपील किया गया।इस अवसर पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दिशा संस्था से राजाराम, ब्लॉक कम्युनिटी प्रक्रिया मैनेजर अर्चना सिंह, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर अफजल मौजूद रहे।

डॉ. प्रशान्त श्रीवास्तव ने नीट परीक्षा में 72 वां स्थान प्राप्त देवरिया जिले का मान बढ़ाया

सिटी रिपोर्टर प्रत्यूष पाण्डेय

देवरिया। डॉ. प्रशान्त श्रीवास्तव ने नीट सुपर स्पेशलिटी की राष्ट्रीय परीक्षा में परचम लहराया। राष्ट्रीय स्तर पर हुई इस परीक्षा में 72वां स्थान प्राप्त कर लखनऊ के प्रतिष्ठित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में पल्मोनरी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर में डीएम कोर्स में प्रवेश लिया और देवरिया जिले का मान बढ़ाया। देवरिया जिला में जीवन मार्ग सोफिया कालेज से दशवीं पास कर शिक्षा प्राप्त की। पिता श्री राकेश श्रीवास्तव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देवरिया से एलडीएम अधिकारी पद से सेवानिवृत्त है। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने ने जिले में सोशल कार्यों एवं बैंकिंग ट्रेनिंग में देवरिया जिले व प्रदेश में अपना योगदान देते रहे हैं। इनके बड़े सुपुत्र शुभम श्रीवास्तव ने केजीएमयू लखनऊ से डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ कर अब बीएचयू में फैकल्टी आर्थोपेडिक सर्जन के रूप में सेवा दे रहे हैं। डॉ शुभम श्रीवास्तव ने भी सरस्वती विद्यामंदिर से 12 तक की शिक्षा प्राप्त की।

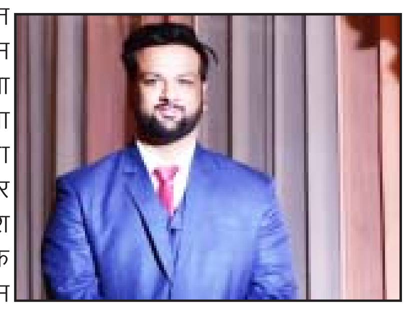

सीएमओ ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण

अयोध्या।शुक्रवार को सीएमओ डॉ सुशील कुमार बानियान ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,मिल्कीपुर एवं सोहावल का निरीक्षण किया।इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सभी जांचे की जाती है एवं आवश्यकतानुसार निःशुल्क अल्ट्रा साउंड कराया जाता है।इसके साथ ही जिन महिलाओं में खून की कमी होती है उनको आयरन सुक्रोज इन्फ्यूशन किया जाता है एवं सभी गर्भवती महिलाओं को जलपान की व्यवस्था की जाती है। आज के दिन सभी गर्भवती महिलाओं को पूरी एवं सब्जी दिया गया।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मिल्कीपुर मे सीएमओ ने दवा वितरण, स्टॉक रजिस्टर आदि को गहनता से देखा।स्टॉक रजिस्टर में भिन्नता पाई गई। फार्मासिस्टों पर कार्यवाही करने का आदेश

दिया इसके साथ ही वहां पर आए लाभार्थियों से मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के विषय में जाना।इसके अतिरिक्त उनके निर्देशन में माननीय काशीराम कालोनी में वृहद टीकाकरण का कार्यक्रम किया गया।कांशीराम कालोनी को 100 ब्लॉकों में विभाजित कर 15 टीम बनकर टीकाकरण का कार्य किया गया।आज कुल 258 लोगो को वैक्सीन लगाई गई।

संस्कृति,विरासत एवं तहजीब का प्रतीक है जौनपुर–प्रभात सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, । मोहम्मद हसन पी. जी. कॉलेज, जौनपुर के सौदागर हाल में "1947 के बाद बदलता जौनपुर" विषय पर एक सारगर्भित संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन जौनपुर के ऐतिहासिक विकास, सामाजिक परिवर्तन तथा प्रशासनिक भूमिका पर केंद्रित रहा, जिसमें विद्वतजनों एवं प्रशासनिक अनुभवी वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे साहित्यकार एवं संपादक प्रभात सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद जौनपुर ने न केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखा, बल्कि शिक्षा, पत्रकारिता और जनजागरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति भी की। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे इतिहास को केवल पढ़ें नहीं, बल्कि उससे सीख लेकर समाज को दिशा दें। विशिष्ट अतिथि विनय सिंह (सेवानिवृत्त मजिस्ट्रेट) ने कहा कि आज का जौनपुर प्रशासनिक दृष्टि से अधिक सक्षम, उत्तरदायी और पारदर्शी हो चुका है, किन्तु जन–भागीदारी ही स्थायी विकास की कुंजी है। वहीं, संजय सिंह (सेवानिवृत्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिहार) ने कानूनी समझ और नागरिक कर्तव्यों की ओर युवाओं का ध्यान आकृष्ट करते हुए संविधान की आत्मा को आत्मसात करने का आह्वान किया। अध्यक्षता कर रहे शायर अहमद निसार ने जौनपुर की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक सहिष्णुता और गंगा–जमुनी तहजीब पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे सामाजिक समरसता, सत्यनिष्ठा और आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य का निर्माण करें। प्राचार्य डॉ.अब्दुल कादिर खान ने अपने उद्बोधन में कहा कि दृइस प्रकार की संगोष्ठियाँ युवाओं को केवल जानकारी ही नहीं देतीं, बल्कि उन्हें संवाद, विमर्श और विवेकशीलता की दिशा में अग्रसर करती हैं। मोहम्मद हसन पी.जी. कॉलेज ज्ञान के साथ–साथ चरित्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के मूल्यों को भी विद्यार्थियों में विकसित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है।" कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए मास्टर आर्ट ताइक्वांडो प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया, जिसमें आत्मरक्षा, अनुशासन, संयम और आत्मविश्वास पर बल दिया गया। प्रशिक्षण में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ताइक्वांडो शिविर ने शारीरिक सशक्तिकरण के साथ मानसिक दृढ़ता का भी संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन अहमद अब्बास खान ने किया

कार्यक्रम में कैलाश सिंह,अभिषेक मिश्रा, जितेंद्र दुबे,रुद्र प्रताप सिंह,अब्दुल हक अंसारी,हसनैन कमर दीपू, ताइक्वांडो कोच संजीव साहू,प्रधानाचार्य मोहम्मद नासिर खान,डॉ जीवन यादव,आर.पी सिंह,डॉ नीलेश सिंह,डॉ विवेक विक्रम सिंह,प्रवीण यादव,संतोष सिंह,तकरीम फातिमा महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण,छात्र–छात्राएँ, शोधार्थी,और गणमान्य नागरिकों की सहभागिता उल्लेखनीय रही। संगोष्ठी का समापन धन्यवाद ज्ञापन एवं राष्ट्रगान के साथ किया गया।

नकली नोटों का कारोबार करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अयोध्या। नकली जाली नोटों का कारोबार करने वाले एक आरोपी युवक को थाना राम जन्मभूमि पुलिस ने गिरफ्तार किया।थाना राम जन्मभूमि पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके नकली नोटों के सप्लायर के तार पड़ोसी देश नेपाल से जुड़े होने के पुख्ता सबूत मिले हैं।शुक्रवार को अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ी क्षेत्र नजर बाग में अर्जुन कॉस्मेटिक की दुकान पर जब युवक ने 500 का नोट देकर एक चाबी का छल्ला खरीदा तो इसके बाद दुकानदार ने 500 का नोट जब हाथ में लिया तो उसे नोट में कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई।इसको लेकर दुकानदार ने युवक से कहा कि ये नोट कुछ गड़बड़ लग रही है। दुकानदार ने अपने पड़ोसी दुकानदार को वहीं नोट दिखाया। दुकानदार के मुताबिक जब वह दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार को उस नोट को दिखा रहा था तभी दूर खड़े नकली नोट के सौदागर के भाई ने अपने भाई को इशारा किया और वो मौके से भीड़ में गुम हो गया।इधर दुकानदार जब वापस अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो युवक वहां से फरार हो गया।यह बात दुकानदार ने अपने आसपास के दुकानदारों से बताई। इसके बाद सभी लोगों ने दर्शन मार्ग पर ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों से पूरी बात बताई और युवक द्वारा दी गई 500 रुपए के जाली नोटों को भी पुलिस को दिखाया।इसके बाद पुलिस ने दुकानदार से युवक का हुलिया और पहनावा पूछा पुलिस ने 500 सौ के जाली नोटों को अपने कब्जे में ले लिया।इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पूरे मेला क्षेत्र में उसे संदिग्ध युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।इसके बाद अयोध्या जिले के राम जन्मभूमि थाने में वार्ड नंबर 13 डढ़िया, थाना सेमरा बाजार बेतिया बिहार के रहने वाले राजा बाबू को पुलिस ने हिरासत में लिया है।इस संबंध में थानाध्यक्ष राम जन्मभूमि अभिमन्यु शुक्ला ने बताया कि इस मामले में शामिल आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है।उन्होंने बताया कि युवक के पास से पुलिस को 500, 500 के 10 जाली नोट बरामद हुए हैं।गिरफ्तार किये गये आरोपी युवक ने कबूल किया है कि उसके पिता नेपाल से भारत नकली नोट लेकर आते हैं।उसको अपने दोनों बेटों को देते है कि उसको बाजार में असली नोटों की तरह ही खरीदारी में इस्तेमाल करें।उन्होंने बताया कि अन्य वांछित आरोपी को पुलिस शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेगी।

विद्यालयों के अवैध संचालन पर खंड शिक्षा अधिकारी हुए शक्त, दो शिक्षण संस्थानों पर गिरी गाज

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। जनपद में खंड शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार यादव द्वारा अमान्य विद्यालयो के निरीक्षण अभियान के तहत दो शिक्षण संस्थाओं पर कार्रवाई की गई है, जो मान्यता से अधिक कक्षाओं का अवैध रूप से संचालन कर रही थीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ष्माँ शीतला गुरुकुल, नेवादाईश्वरीसिंहष को केवल कक्षा 5 तक की मान्यता प्राप्त थी, जबकि विद्यालय में कक्षा 12 तक पठन–पाठन कार्य अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। जांचोपरांत उच्च कक्षाओं का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया। इसी क्रम में षशिवशक्ति पब्लिक स्कूलष, जिसे केवल कक्षा 6 से 8 तक संचालन की अनुमति थी, को भी मान्यता की सीमा से अधिक गतिविधियों के चलते बंद करा दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता की शर्तों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई अन्य विद्यालय भी इसी प्रकार का अवैध संचालन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जाएगी।

आध्यात्मिक संत प्रेम रावत जी ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना) न्यू वेंचर प्रेम रावत डाटकॉम सपोर्ट टीम के बैनर तले आज नगर के एस आर जे लान में गुरु पूजा महोत्सव कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टाइमलेस टुडे डाट टीवी के द्वारा प्रसारित किया गया। कार्यक्रम में विश्व शांति शिक्षा कार्यक्रम के संस्थापक एवं विश्व शांति दूत मोटिवेशनल स्पीकर आध्यात्मिक संत प्रेम रावत जी ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। अपने 70 मिनट के लाइव संबोधन में उन्होंने अपने अनुयायियों को गुरु और शिष्य के रिश्ते को समझाया कार्यक्रम के बाद भव्य पूजन गैलरी में भक्तों के द्वारा पूजा की गई । कार्यक्रम की शुरुआत में लान के मुख्य द्वार पर श्रावण मास के पवित्र महीने में कावड़ियों के लिए भंडारा किया गया जिसमें तहरी का वितरण किया गया कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती अलका गुप्ता ने दीप प्रज्वलित किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपनी प्रतिभाओं का जलवा बिखरने वाले नौनिहालों को मेडल पहरा कर उत्साह वर्धन किया आयोजकों द्वारा श्रीमती गुप्ता को विश्व शांति शिक्षा कार्यक्रम के संस्थापक प्रेम रावत जी द्वारा लिखित पुस्तक स्वयं की आवाज भेंट की गई तथा उनका स्वागत अंजलि और पूर्णिमा के द्वारा बुके देकर किया गया कार्यक्रम के बाद अतिथियों ने भोजन और मिष्ठान का आनंद लिया कार्यक्रम के दौरान ही हुई बारिश में भक्ति के भजनों पर अनुयाई थिरकते नजर आए। कार्यक्रम को बृज किशोर दीक्षित रामबरन वर्मा, मनोज, दीप कुमार सोनी सुशील कुमार श्रीवास्तव और पीके गुप्ता ने संबोधित करते हुए गुरु पूजा के महत्व पर प्रकाश डाला कार्यक्रम का संचालन अस्मिता गुप्ता ने किया कार्यक्रम में सेवा टीम के द्वारा सेवा और सहयोग के द्वारा कार्यक्रम सफल किया गया।

दो अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि की 20 वी किस्त होगी जारी – सीडीओ

अयोध्या। मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि दिनांक 02 अगस्त को वाराणसी में आयोजित होने वाले पीएम किसान उत्सव दिवस में प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की जायेगी। यह कार्यक्रम जनपद, विकास एवं पंचायत स्तर पर कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।उन्होंने बताया कि वर्चुवल रूप से ीजजचेरूध्ध्चउपदकपूंमइबेंज.दपब. पद लिंक पर किसान सम्मान समारोह का प्रसारण होगा।जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर कार्यक्रम को प्रभावी बनाये जाने हेतु कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से आयोजित होगा जिसमें स्थानीय जन प्रतिनिधियों यथा–लोकसभा/विधानसभा/विधान परिषद इत्यादि की भी कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित किया जाय।यह कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक स्थानीय स्तर पर किया जायेगा।उसके बाद मुख्य कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों से सम–सामयिक तकनीकी चर्चा का सत्र भी चलाया जाय।जनपद एवं विकास खण्ड मसौधा का कार्यक्रम संयुक्त रूप से कृषि विज्ञान केंद्र मसौधा में एवं अन्य विकास खण्डों में कार्यक्रम विकासखण्ड मुख्यालय पर कराया जायेगा। उपरोक्त कार्यक्रम के आयोजन हेतु जनपदध्विकासखण्ड स्तर पर उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी सदर एवं सहायक विकास अधिकारी कृषि को नोडल अधिकारी नामित किया गया है एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है।सभी क्षेत्रीय कर्मी विभिन्न ग्रामों में प्रगतिशील कृषकों को कार्यक्रम का लिंक भेजकर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करायें ताकि ग्राम स्तर से भी किसानों की सहभागिता सुनिश्चित हो सकें।

शिक्षक संघ पाण्डेय गुट ने डीआईओएस को सौपा ज्ञापन

अयोध्या। गुरुवार को उ0प्र0मा0 शिक्षक संघ पाण्डेय गुट ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर शिक्षक समस्याओं का नौ सूत्रीय मांग पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक डाक्टर पवन कुमार तिवारी को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौपा।जिला विद्यालय निरीक्षक ने संगठन को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही उक्त समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। संगठन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि यदि शीघ्र ही समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो अगस्त माह में शिक्षा भवन पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन देने एवं वार्ता में मण्डलीय मंत्री उदय नारायण तिवारी, जिला मंत्री अमरनाथ नाथ सिंह, नगर मंत्री अक्षतेशवर दूबे, कार्यकारी मंत्री अंकुर तिवारी, घनश्याम तिवारी, महंत रामभद्रदास, सतीश सिंह,चन्द्र कमल वर्मा, डा0 रंजीत, सुरेश सिंह, जियाराम वर्मा, दिलीप द्विवेदी,विजय द्विवेदी, राजेश वर्मा एवं समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

मेगा हेल्थ कैंप एवं नियमित टीकाकरण का हुआ आयोजन

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुशील कुमार बनियान के मार्गदर्शन में ब्लॉक मसौधा के अंतर्गत भदरसा नगर पंचायत के जे ए बी इंटर कालेज में मेगा हेल्थ कैंप एवं नियमित टीकाकरण का आयोजन किया गया।मेगा हेल्थ कैंप के मुख्य रूप से आए हुए 1783 लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन किया गया।जरनल ओ पी डी 549, डेंटल स्क्रीनिंग –41, एनसीडी कार्यक्रम के अंतर्गत एन सी डी स्क्रीनिंग 101, मलेरिया जांच 52, लैब जांच–148, आयुष्मान्य भारत के अंतर्गत 58 बुजुर्गों के कार्ड बनाए गए।इसके अलावा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम एवं 56 लोगो को टेली मानस के टोल फ्री नो 14416 पर कॉल करने पर किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या का निदान संभव है। कॉल निःशुल्क तथा कॉलर को गोपनीयता बनी रहती है।आरबीएसके टीम द्वारा 250 आए हुए रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सक्रिय क्षय रोगी अभियान के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया गया।32 गर्भवती महिलाओं की जांच एवं 55 परिवारों को परिवार नियोजन के महत्व के में बारे बताया गया साथ ही जनरल ओ पी डी की गई।बच्चों एवं वयस्क का निःशुल्क नेत्र परीक्षण –76 किया गया साथ ही संबंधित रोगियों को निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 372 बच्चो को टीकाकरण किया गया , आभा पक–156 की बनी,साथ ही संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत नगर पंचायत में बच्चों की रैली निकाली गई लोगो को इसके प्रति जागरूक किया गया।इस मेगा हेल्थ कैंप में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आशुतोष श्रीवास्तव, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ पी सी भारती, डिप्टी सीएमओ डॉ दीपक पांडे, डिप्टी सीएमओ डॉ राजेश चौधरी ,डीएचईआईओ डी पी सिंह, डिस्ट्रिक्ट एआरओ प्रवीण त्रिपाठी , डीपीएम राम प्रकाश पटेल, डीसीपीएम अमित आरबीएसके मैनेजर डॉ हम्माद, मो हॉरिस ,मनोज मौर्य, सुशील वर्मा, यदुवीर सिंह , जेएसआई अनुराग पीएसआई इंडिया प्रवीण दीक्षित एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसौधा से अधीक्षक डॉ प्रदीप कुमार, एच ईओ राजीव कुमार, एआरओ वंदना,मो अफजल,अर्चना सिंह एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

अपराधियों का लिये शरणगाह बने कालोनी के खाली व जर्जर भवन

अयोध्या।अयोध्या कैंट के कई कालोनियों में खाली पड़े खंडहर मकान अपराध बढ़ने का मुख्य कारण बन रहा है। क्योंकि शाम ढलते ही इन खंडहर मकानों में आपराधिक किस्म के लोग जाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए रणनीति बनाते हैं।इसके अलावा वही कुछ युवा नशे का भी सेवन करते हुए दिखाई देते हैं।जिसके चलते इसका विरोध कई बार इन कालोनियों के लोगों ने किया परंतु इन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा रहा है। वही इन कालोनियों के संबंधित चौकियों के प्रभारी व पुलिस कर्मी देर शाम व रात को हूटर बजाकर – अपने कार्यों की खानापूर्ति कर लेते हैं।जिससे इन कालोनियों के खंडहर मकानों में बेधड़क आपराधिक किस्म के लोग रात भर विचरण करते रहते हैं।बताते चलें ये जर्जर मकान विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित है जो कि अब नगर निगम में शामिल है।शहर के कई कालोनियों में दर्जनों ऐसे मकान है,जिन्हें तो लोग खरीद लिये है।परंतु वहां पर न रहकर कही और जगह पर रह रहे हैं।वहां के स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मकान के स्वामी इस मकान में साल दो साल में एकाध बार आकर

देख जाते हैं,जिसके चलते वह मकान खंडहर में तब्दील हो गया है।परिणाम स्वरूप इन खंडहर मकानों में शाम से देर रात तक आपराधिक किस्म के लोगो का जमावड़ा लगा रहता है।इस संबंध में इन कालोनियों के निवासियों का कहना है कि यह एक बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है।खासकर शाम को लड़कियों व महिलाओं को यहां पर सक्रिय आपराधिक किस्म के लोगो से खतरा भी बना रहता है।इन कालोनियों के लोगों ने बताया कि आये दिन इन कालोनियों में चौन स्नैचिंग, छेड़छाड़ व मारपीट की घटनाएं होती रहती है।इन लोगों का कहना है कि इससे संबंधित चौकी प्रभारी, पुलिस कर्मी, चीता मोबाइल पुलिस कर्मी के साथ साथ यूपी 112 के पुलिस कर्मी कभी भी इन स्थानों पर आना मुनासिब नहीं समझते हैं।इस संबंध में सीओ सिटी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि यह एक गंभीर समस्या है।शीघ्र ही इस तरह के कालोनियों में खाली खंडहर मकानों को चिह्नित किया जायेगा जहां पर इस तरह की वारदात हो रही है।इस तरह के अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर व थाना कैंट के साथ चौकी प्रभारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई जायेगी।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक **देश की उपासना**

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।